कंपनियों से समग्र आधार पर अपेक्षाकृत कम दर पर कर लगाया जाता है। विदेशी कंपनियां निवेश, आय और दीर्घ-कालीन पूंजीगत लाभ पर समग्र आधार पर कर की कम दर की भी पात्र हैं। जहां तक संपत्ति कर का संबंध है, इसमें कोई अंतर नहीं है।

अखबारी कागजों की कीमतों में वृद्धि

1566. श्रीमती सुषमा स्वराज :

श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गत तीन वर्षों में अखबारी कागज की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि नहीं, तो जून, 1991 में देश में उत्पादित सभी किस्म के अखबारी कागजों की क्या-क्या कीमतें थीं ;

(ग) फरवरी, 1995 के प्रथम सप्ताह में उपरोक्त सभी प्रकार के कागजों की क्या-क्या कीमतें थीं ;

(घ) क्या सरकार ने स्वदेश में उत्पादित अखबारी कागजों की कीमतों में हुई वृद्धि के कारणों का पता लगाया है ;

(ङ) देश में कुल कितने अखबारी कागज उत्पादक मिलें हैं, जो निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में चल रही है ;

(च) क्या इन मिलों द्वारा अपनी-अपनी अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता का भरपूर उपयोग किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 में निजी, सहकारी और सरकारी क्षेत्र की इन मिलों द्वारा अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता के उपयोग के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की प्रमुख अखबारी कागज मिलों द्वारा अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि और प्रमुख एककों के संबंध में जून, 1991 तथा फरवरी, 1995 के प्रथम सप्ताह में प्रचलित मूल्यों के बारे में विवरण I (**नीचे देखिए**) संलग्न है।

(घ) अखबारी कागज के मूल्यों में बिजली, आयातित लुगदी, रसायन तथा अन्य कच्ची सामग्री जैसी विविधियों की लागत में वृद्धि के कारण बढ़ोतरी होने की सूचना है। अखबारी कागज के मूल्य पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। स्वदेशी अखबारी कागज के मूल्य में प्रत्येक संशोधन को इसके कारणों और औचित्य के कार्योत्तर अध्ययन के लिए औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो (बी.आई.सी.पी.) को भेजा जाता है।

(ङ) इस समय अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची-1 में 22 मिलें हैं (4 केन्द्र सरकारी क्षेत्र में, 2 राज्य सरकारी क्षेत्र में और 16 निजी क्षेत्र में) जिन्हें अखबारी कागज का विनिर्माण करने वाली मिलों के रूप में घोषित किया गया है।

(च) और (छ) सरकारी क्षेत्र में प्रमुख अखबारी कागज मिलों और औरंगाबाद पेपर मिल्स लि. द्वारा क्षमता के उपयोग से संबंधित विवरण -II (नीचे देखिए) संलग्न है। निजी क्षेत्र की अन्य अखबारी कागज मिलों को 1993 के बाद से अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है। इसलिए इन मिलों के क्षमता उपयोग के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

विवरण-I

प्रमुख अखबारी कागज मिलों द्वारा अखबारी कागज के मूल्य में की गई वृद्धि

मिल का नाम	वृद्धि की तारीख	मूल्य में वृद्धि (रु० प्रति मी. टन)
तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट एण्ड पेपर लिमिटेड (टी.एन.पी.एल.)	20-95-1992	1000
	20-06-1993	500
	10-10-1994	1430
	07-12-1994	1530
	25-02-1995	2475
दि मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड (एम.पी.एम.)	21-05-1992	1040
	24-11-1992	922
	07-10-1994	1523
	10-12-1994	1200
	15-02-1995	2250
हिन्दुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड (एच.एन.एल.)	20-05-1992	1000
	21-06-1993	1000
	10-10-1994	1300
	12-12-1994	1150
	21-02-1995	2500
नेपा (एन.ई.पी.ए.) लिमिटेड	22-05-1992	1700
	02-12-1992	1000
	12-10-1994	1200
	10-11-1994	500
	12-12-1994	1500
	01-02-1995	1500

मिल का नाम	जून, 1991 के दौरान अखबारी कागज का मूल्य (रु० प्रति मी० टन)	फरवरी, 1995 के प्रथम सप्ताह में अखबारी कागज का मूल्य (रु० प्रति मी० टन
तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट एण्ड पेपर लिमिटेड (टी.एन. पी.एल.)	17,570	21,700

दि मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड (एम.पी.एम)	17,215	21,900
(हिन्दुस्तान) न्यूज़प्रिंट लि. (एच.एन.एल.) नेपा लिमिटेड	16,555	21,000
	15,700	22,500

विवरण-II

सरकारी क्षेत्र की अखबारी कागज मिलों की क्षमता का उपयोग

क्रम सं०	मिल का नाम	क्षमता उपयोग (प्रतिशत में)		
		1991-92	1992-93	1993-94
1.	हिन्दुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड	113	121	123
2.	मैसूर पेपर मिल्स	110	104	115
3.	नेपा लिमिटेड	85	85	75
4.	तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट एण्ड पेपर्स लिमिटेड	76	81	68
5.	औरंगाबाद पपर मिल्स लिमिटेड	—	—	71

Manufacture of colour photo films

1567. SHRI V. GOPALSAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 753 given in the Rajya Sabha on the 28th November, 1991 and state:

(a) whether the proopsal to manufacture colour photo films has been included in the Eighth Plan proposals;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) what will be the resources required for this project at the Hindustan Photo film Manufacturing Company Limited at Udhagamandalam?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) No, Sir.

(b) Resource constraints.

(c) The cost of the project may be *of* the order of Rs. 300 crores.

Schemes started by FIPB

1568. DR. RANBIR SINGH:

SHRI RAMNATH KOVIND:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Foreign Investment Promotion Board has started several schemes consisting of forestry, hydro-electricity, horticulture and mining in the hill regions of Himachal Pradesh;

(b) whether Government would start the said schemes in the hill regions of other Spates, particularly in Kumaon region of U.P. by asking the proposal from Finland, New Zealand, Switzerland etc.: and